

## The country aims to be 'a leader in thought and action on climate', its foreign secretary says

*Harsh V. Shringla is India's Foreign Secretary.*

Five years after the Paris Agreement, India is among the few developing countries that are not only meeting their “green” targets but are aspiring to more ambitious climate goals.

At the recent Climate Ambition Summit, Prime Minister Narendra Modi articulated the Indian approach. He said that we must set our sights “even higher”, even as we do not lose sight of the past. He added that India would not only achieve its Paris Agreement targets, but would exceed them.

At the U.N. Climate Action Summit in 2019, Modi said that an ounce of practice is worth more than a ton of preaching. We are taking practical steps across all areas, including energy, industry, transport, agriculture and protection of green spaces, in our whole-of-society journey to become a leader in climate action and climate ambition.

India recognizes that climate change cannot be fought in silos. It requires an integrated, comprehensive and holistic approach. It requires innovation and adoption of new and sustainable technologies. Conscious of these imperatives, India has mainstreamed climate in its national developmental and industrial strategies.

Energy is at the center of all climate strategies. We believe India has become a clean energy powerhouse and is a leader in energy transition from carbon dioxide-producing sources to renewables and non-fossil-fuel sources.

We intend to keep harnessing India's renewable energy potential. Our renewable energy capacity is the fourth largest in the world and the capacity expansion being undertaken is also one of the largest in the world. The bulk of this will come from the cleanest energy source, the sun.

We are seeing progress already. We initially committed to 175 GW of renewable energy capacity by 2022. We have gone further and expect to cross 220 GW in the next two years. We have an even more ambitious target of 450 GW by 2030.

We are working to ensure that 40% of electric power in India is from non-fossil fuel sources by 2030. This clean energy push goes hand-in-hand with a parallel effort to reduce the emissions intensity of our economy by 33-35% (from 2005 levels) by 2030.

The Ujala scheme – a national drive to use LED lamps – is reducing CO2 emissions by 38.5 million tonnes every year. The Ujjwala scheme, under which over 80 million households have been provided access to clean cooking gas, is one of the largest clean energy initiatives in the world.

Climate action and sustainability is being brought into government schemes across multiple sectors. Our Smart Cities Mission is working with 100 cities to help them become more sustainable and adaptable to the challenges of climate change. The National Clean Air Programme aims to reduce air pollution (PM2.5 and PM10) by 20-30% in the next four years.

The Jal Jeevan Mission, which aims to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections by 2024 to all households in rural India, has a strong sustainability focus.

More trees are being planted and degraded land is being reclaimed to create a carbon “sink” that can absorb 2.5-3 billion tonnes of CO2.

We are also working rapidly to create a green transport network, to offset a sector known for its polluting emissions particularly in our big cities.

India is building next-generation infrastructure such as mass transit systems, green highways and waterways. A national electric mobility plan is creating an e-mobility ecosystem with the aim to have over 30% of all vehicles on India's roads to be electric.

These initiatives are for our own good as India is among the countries most vulnerable to the impact of climate change.

We recognise there is still a long way to go but these efforts are already paying dividends. India’s emission intensity has reduced by 21% over the period 2005-2014. Over the next decade, we are expecting even greater reductions.

India intends to be a responsible global citizen in the climate space. We are not only going beyond our Paris Agreement commitments. We are adopting innovative instruments to further international cooperation in climate action.

We have created international organisations like the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure that are working on creating global low-carbon pathways. More than 80 countries have joined the International Solar Alliance, making it one of the fastest-growing international bodies.

This combination of national action and responsible international citizenship makes India unique amongst developing countries and is placing it on the path to realise its ambitions to be a leader in thought and action on climate.

*Harsh Vardhan Shringla is Foreign Secretary of India. Views expressed are personal.*

<https://news.trust.org/item/20210121095650-7f4b9>

## पेरिस समझौते के आगे की राह, भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बनना चाहता है दुनिया का एक जिम्मेदार देश

भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन गया है और कार्बन डाईऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से निकल कर अक्षय और गैर-जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने में अग्रणी देश है।

**[हर्षवर्धन शृंगला]**। पेरिस समझौते के पांच वर्षों के बाद भारत उन कुछेक विकासशील देशों में से एक है, जो न केवल अपने 'पर्यावरण संरक्षण' संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि जलवायु संबंधी साध्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं। हाल में जलवायु आकांक्षाओं से जुड़े शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दृष्टिकोण को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें अतीत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 'और बड़े लक्ष्यों' को दृष्टि में रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संरक्षण शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किया गया थोड़ा-सा भी काम ढेरों उपदेशों से कहीं अच्छा होता है। हम जलवायु संरक्षण से संबंधित अभियान और आकांक्षाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, कृषि और हरित क्षेत्रों की सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अपने पूरे समाज की इस यात्रा में व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं।

भारत का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन से अलग-अलग बंटे हुए रह कर नहीं लड़ा जा सकता है। इसके लिए एकजुटता के साथ, व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए नवाचारों तथा नई और स्थायी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत है। भारत इन अनिवार्यताओं के प्रति सचेत है और इसीलिए भारत ने अपनी राष्ट्रीय विकासात्मक और औद्योगिक रणनीतियों में जलवायु को शामिल किया है।

### अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर

ऊर्जा जलवायु संबंधी सभी रणनीतियों का केंद्रीय बिंदु है। हमारा मानना है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन गया है और कार्बन डाईऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से निकल कर अक्षय और गैर-जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने में अग्रणी देश है। हमारा उद्देश्य भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करते रहना है। अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। अक्षय ऊर्जा के इस क्षेत्र में जिस प्रकार का क्षमता विस्तार किया जा रहा है, वह भी दुनिया में सबसे बड़े प्रयासों में से एक है। इसका सबसे बड़ा भाग सूर्य से प्राप्त होगा, जो ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है। हम इस दिशा में पहले ही प्रगति पर हैं। शुरू में हम वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। हम इससे भी आगे बढ़ गए हैं और हमें विश्वास

है कि हम अगले दो वर्षों में 220 गीगावाट क्षमता प्राप्त कर लेंगे। हमारा 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता संस्थापित करने का और भी बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

### **उज्ज्वला योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहल में से एक**

हम वर्ष 2030 तक भारत में 40 प्रतिशत बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा का यह अभियान वर्ष 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन की तीव्रता को 33-35 प्रतिशत (2005 के स्तर की तुलना में) तक कम करने के प्रयासों के साथ-साथ चलता रहेगा। उजाला योजना एलईडी लैंप उपयोग करने का एक राष्ट्रीय अभियान प्रति वर्ष कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को 3.85 करोड़ टन कम कर रही है।

उज्ज्वला योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहल में से एक है, जिसके तहत आठ करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस की सुविधा प्रदान की गई है। कई क्षेत्रों में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में जलवायु संबंधी अभियान और इसके स्थायित्व को शामिल किया जा रहा है।

### **जल जीवन मिशन पर दिया जा रहा जोर**

हमारा स्मार्ट सिटी मिशन सौ शहरों में चल रहा है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समक्ष अधिक स्थायी और नई परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनीय बन सकें। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य अगले चार वर्षों में वायु प्रदूषण (पीएम 2.5 और पीएम 10) को 20-30 प्रतिशत तक कम करना है। जल जीवन मिशन में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि घरों में हमेशा जल उपलब्ध रहे, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। कार्बन को अवशोषित करने के लिए और अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं और बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जा रहा है, जो 2.5-3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं।

### **ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का निर्माण करने की दिशा में तेजी से हो रहा काम**

हम विशेष रूप से अपने बड़े शहरों में प्रदूषण उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी सेक्टर के प्रभाव को कम से कम करने के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का निर्माण करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भारत मॉस ट्रांजिट सिस्टम, ग्रीन हाईवे और जलमार्गों जैसे अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान एक ई-मोबिलिटी अवसंरचना तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत के कुल वाहनों में से 30 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक हों। ये पहल हमारी भलाई के लिए ही हैं, क्योंकि भारत उन देशों में से एक है, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। हम यह जानते हैं कि हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हमारे इन प्रयासों से लाभ मिलना आरंभ हो गया है। वर्ष 2005-2014 की अवधि के दौरान भारत की उत्सर्जन मात्रा में 21 प्रतिशत की कमी आई है। अगले दशक तक हम इसमें और भी अधिक कमी की उम्मीद कर रहे हैं।

## 80 से अधिक देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में हुए शामिल

भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दुनिया का एक जिम्मेदार देश बनना चाहता है। हम न केवल पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं से भी अधिक कार्य कर रहे हैं, बल्कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में की जाने वाली कार्रवाई के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए परिवर्तनकारी साधन अपना रहे हैं। हमने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए हैं, जो वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित समाधान तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 80 से अधिक देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिससे यह तेजी से विस्तार पाने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार देश होने के कारण भारत विकासशील देशों में अद्वितीय बन गया है। इससे भारत जलवायु परिवर्तन पर अपनी सोच रखने और यथोचित कार्रवाई करने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की राह पर अग्रसर हो रहा है।

[हर्षवर्धन शृंगला]

(लेखक भारत के विदेश सचिव हैं)

[लेखक के निजी विचार हैं]

(<https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-path-ahead-of-the-paris-agreement-india-wants-to-be-a-responsible-country-in-the-field-of-climate-change-21315339.html> )